हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-26 शिमला शुक्रवार,12 ls 18 vizSy 2024 आरएनआई एचपीएचआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

कंगना ही बता सकती हैं देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम : सीएम सुक्खू

vkdlk gehjiqjA देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत के पिछले दिनों दिए बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुटकी ली है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे यह तो कंगना रणौत ही बता सकती हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमलावर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सर्किट हाउस हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव में नाक बचाने के लिए जयराम नौटंकी पर उतर आए हैं।

सत्ता की भूख पूरी न होने पर बिके हुए विधायकों को साथ लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के पांव पकड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं।

जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते हमीरपुर जिला की याद नहीं आई। मुख्यमंत्री बनने पर वह समीरपुर में नहीं पहुंचे। अब उनको हमीरपुर की याद आ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले के विधायकों को भाजपा सरकार में जयराम से मिलने का समय नहीं मिलता था। 15 साल पूर्व जिस बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया था, उसका काम कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। बड़सर से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोई नई नवेली दुल्हन बन रहा है।

यह सारी नौटंकी जयराम ठाकुर चुनाव में नाक बचाने के लिए कर रहे हैं। 1 जून को जनता तय कर देगी कि उन्हें बिकने वाले विधायक चाहिए या फिर ईमानदार।

प्रत्याशियों के नाम के एलान में देरी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव में अभी 50 दिन हैं, जल्द ईमानदार और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी चुनाव में उतारे जाएंगे।

गोमांस के मुद्दे पर बोले सीएम, भाजपा को देना होगा जवाब

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत के गोमांस खाने के मुद्दे पर कहा कि सनातन धर्म में गोमांस नहीं खाया जाता।

यदि किसी ने यह कहा है कि उन्होंने गोमांस खाया है तो क्यों खाया है। भाजपा को इस विषय पर जवाब देना होगा।

f'keyk ykdlHkk lhV ls foukn lqYrkuiqjh vkSj eaMh ls foØekfnR; flag gksaxs çR;k'kh % eqds'k vfXugks=h

vkdlk ÅukA हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला लोकसभा सीट से विनोद सुल्तानपुरी, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और कुटलैहड़ विधानसभा उपचुनाव में विवेक शर्मा हमारे प्रत्याशी होंगे।

दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव तो जीतेगी ही। इसके बाद निर्दलीय विधायकों वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों सहित शिमला ग्रामीण और कसौली में भी कांग्रेस पार्टी पांच चुनावों में जीत दर्ज करेगी।

वह ऊना के जोगीपंगा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कंगना रणौत चाहती थीं कि युवा उम्मीदवार को उतारा जाए। इसके लिए मंडी से प्रतिभा सिंह की जगह युवा उम्मीदवार के तौर पर विक्रमादित्य सिंह को उतारा जा रहा है।

हमीरपुर से संभावित प्रत्याशी सतपाल रायजादा हैं। हालांकि अभी तक अंतिम मुहर सीईसी की बैठक में औपचारिकता के तौर पर लगना बाकी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की सरकार मजबूत है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिर सरकार को गिराने के पीछे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पूरा हाथ था, लेकिन अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा का लोटस मिशन पूरी तरह से असफल रहा है।

उन्होंने कहा है कि इस पूरे कारनामे के पीछे आर्किटेक्चर और डिजाइनर भाजपा के ही लोग थे और भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के ही बागी विधायकों को टिकट देकर यह बात पूरी तरह से साबित कर डाली है।

भाजपा के ही वरिष्ठ नेता अब बागी विधायकों को पचा नहीं पा रहे हैं। डिप्टी सीएम कुटलैहड़ कांग्रेस को एकजुटता का पाठ पढ़ा गए।

कहा कि यह उपचुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस के बागियों के बीच हैं, क्योंकि भाजपा के पास न तो प्रत्याशी हैं और ही भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है।

25 विधायकों वाला विपक्ष सत्ता के सपने देख रहा है।

एचपीयू से संबद्ध कॉलेज लेंगे चार वर्षीय ऑनर्स, रिसर्च डिग्री शुरू करने पर फैसला

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2024–25 से संबद्ध कॉलेजों में एनईपी–2020 को लागू करने के लिए सिलेबस को तैयार कर उसे मंजूर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है।

नीति के अनुसार चार वर्षीय यूजी डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में ही शुरू की जा सकेगी। कॉलेज ही ऑनर्स, रिसर्च डिग्री देने को उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही विश्वविद्यालय से इसके लिए अनुमति लेंगे।

अधिकतर कॉलेज तीन साल की ही यूजी डिग्री कोर्स को करवाना जारी रखेंगे। एनईपी के लागू होने पर यूजी छात्रों के पास तीन या चार साल की डिग्री पूरी करने की अवधि में बीच में डिग्री को अधूरी छोड़ फिर से कुछ अंतराल के बाद उसे पूरा करने की सुविधा जरूर मिलेगी।

एक साल यानि दो सेमेस्टर पूरे करने पर छात्र को यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।इसमें छात्र को 40 क्रेडिट और वोकेशनल कोर्स के चार क्रेडिट प्राप्त करने ही होंगे। दो साल यानि चार सेमेस्टर पूरे करने और 80 क्रेडिट और चार वोकेशनल कोर्स के क्रेडिट प्राप्त करने पर यूजी डिप्लोमा विवि से मिल जाएगा। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को तीन साल के भीतर फिर से अपनी डिग्री की पढ़ाई को पूरा करने को एंट्री करनी होगी।

छात्र को सात साल में अपनी तीन साल की डिग्री पूरी करने को मिलेंगे। यूजी की तीन साल की डिग्री को पूरा करने को छात्र को न्यूनतम 120 क्रेडिट प्राप्त करना जरूरी होगा, जबकि चार वर्षीय यूजी डिग्री शुरू करने पर छात्र को न्यूनतम 160 क्रेडिट प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी उन्हें ऑनर्स, रिसर्च के साथ चार वर्षीय डिग्री विवि से मिल पाएगी।

तीन साल छह सेमेस्टर पूरे करने के बाद छात्र तीन अतिरिक्त कोर्स पढ़कर ऑनर्स या रिसर्च को चुन सकेंगे।

पहले छह सेमेस्टर में 75 फीसदी अंक अर्जित करने वालों को ही रिसर्च डिग्री में प्रवेश

यूजी की चार वर्षीय रिसर्च डिग्री में सिर्फ उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने पहले छह सेमेस्टर तीन साल में 75 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित किए होंगे।

ऐसे छात्रों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज फैकल्टी के तहत रिसर्च करनी होगी। उन्हें इसके 12 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

आनर्स के लिए तीन विषयों में 12 क्रेडिट लेने पर ही डिग्री मिल सकेगी। चार साल की ऑनर्स या विद रिसर्च डिग्री के लिए कॉलेज के पास पुस्तकालय, जर्नल, कंप्यूटर लैब और सॉफ्टवेयर, लैबोरेटरी के अलावा दो स्थायी पीएचडी सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने को फैकल्टी का होना जरूरी होगा।

विवि के अधिष्ठाता अध्ययन और एनईपी–2020 लागू करने को बनी कोर कमेटी के अनुसार यूजी की चार वर्षीय आनर्स और रिसर्च डिग्री के लिए सिलेबस तैयार कर रहा है।

यह कॉलेजों और शिक्षा विभाग, कॉलेजों पर लागू करने पर निर्भर करेगा, कि कौनसा कॉलेज कौनसी डिग्री देगा।

शिमला में पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह के पुत्र सहित 5 लोग किए गिरतार, 42-89 ग्राम चिट्टा पकड़ा

vkdlk f'keykA हिमाचल की राजधानी शिमला में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मंगलवार देर रात पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह के बेटे सहित 5 लोगों को चिट्टे के साथ गिरतार किया।

इनमें एक युवती भी शामिल है।

आरोपियों से 42.89 ग्राम चिट्टा और एक तराजू बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनकी धरपकड़ को जाल बिछाया और देर रात शिमला के पुराना बस अड्डा के साथ एक प्राइवेट होटल में दबिश दी।

इस दौरान आरोपियों से चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों की थार गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है।

इसके बाद इन्हें सदन थाना शिमला ले लिया गया।

सूचना के अनुसार, आरोपी लंबे समय से हिमाचल में चिट्टा सप्लाई कर रहे थे।

पुलिस पूछताछ में कई अहम जानका. रियां मिल सकती है।

ये आरोपी किए गए गिरतार

पकड़े गए आरोपियों में तीन पंजाब, एक चंडीगढ़ और हिमाचल की युवती है।

इनकी पहचान प्रकाश सिंह (37) पुत्र सुच्चा सिंह लंगाह निवासी गुरदासपुर पंजाब के अलावा अजय कुमार (27) पुत्र चमन लाल निवासी नूरखोडियां पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, अवनी (19) पुत्री विकास नेगी गांव सांगला किन्नौर हिमाचल, शुभम कौशल (26) पुत्र संदीप कौशल ब्लॉक ए सेक्टर–1 चंडीगढ़ और बलजिंद्र (22) पुत्र कुलद. ीप सिंह गांव नड्डा मोहाली पंजाब के तौर पर हुई है।

यौन उत्पीडन् का आरोपी मुख्याध्यापक निलंबित प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

vkdlk nnkgw ¼fljekSj½ A सिरमौर जिले के ददाहू क्षेत्र की एक माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत मुख्याध्यापक को विभाग ने निलंबित कर दिया है।

मुख्याध्यापक पर स्कूल के चौकीदार के साथ स्कूल की मूकबधिर महिला कर्मी का यौन उत्पीडन् का आरोप है। इसे लेकर संगडाह पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद अदालत में भेज दिया था। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कार्यवाहक मुख्याध्यापक टीजीटी आर्ट्स गंगाराम को निलंबित करने का फरमान जारी किया। संगडाह पुलिस इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के अनुसार बीते दिनों संगडाह क्षेत्र की एक माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत मूकबधिर महिला कर्मचारी के साथ कार्यवाहक मुख्याध्यापक और चौकीदार द्वारा यौन उत्पीडन् के आरोप लगे थे। शिकायत मिलते ही जहां शिक्षा विभाग कार्रवाई में जुट गया है वहीं संगडाह पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

घटना बीते फरवरी की है। पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है। लिहा. जा बयान कलमबद्ध करने के लिए पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद ली।

सख्ती वाले प्रस्ताव को केंद्र से अभी मंजूरी नहीं, हिमाचल में चिट्टा चाट रही युवा पीढ़ी

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश के लिए चिट्टा तस्करी की समस्या दिन–प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। राज्य का युवा नशे की चपेट में फंस रहा है।

युवाओं के नशे से खोखले होने के साथ सूबे का भविष्य भी संकट में नजर आ रहा है।

राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही हो या भाजपा की, लेकिन बाहरी राज्यों से नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रुक पा रही है।

नशे ने हिमाचल में दशकों से अपनी जड़ें जमा रखी हैं।

चरस–अफीम के जाल से ही राज्य बाहर नहीं निकल पाया था कि अब सिथेंटिक नशा चिट्टा युवाओं के लिए खतरा बन गया है। जनता सांसदों को भी इसी उम्मीद के साथ चुनती है कि वे नशे से खोखला होते हिमाचल का मुद्दा संसद तक ले जाएंगे, मगर यह अपेक्षाएं अधूरी हैं।

युवतियां भी आ रही हैं नशे की चपेट में।

चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके खात्मे के लिए हर स्तर पर उठानी होगी आवाज।

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आरोपियों की 14.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

इन मामलों में जो आरोपी गिरतार हुए हैं, उनमें 2 हजार 136 पुरुष और 79 महिलाएं शामिल हैं।

पुलिस दावे करती रही है कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा की तस्करी के स्रोत अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि हैं। ड्रोन की मदद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों तक चिट्टा पहुंचाया जा रहा है।

इसके बाद यह हिमाचल की सीमाआ. ` तक पहुंच रहा है।

एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश का मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन

प्रदेश सरकार ने सख्ती के लिए केंद्र सरकार से एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है। अभी ये मामला गृह मंत्रालय के विच. ाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ 360 किलोमीटर की सीमा है। चिंता का विषय यह है कि चिट्टा हिमाचल के जनजातीय और दुर्गम इलाकों तक पहुंच रहा है।

बीते तीन साल में हिमाचल में 4 हजार 445 आरोपियों को चिट्टा तस्करी या इसके उपयोग के आरोप में गिरतार किया जा चुका है।

सरकार चिट्टा तस्करों की संपत्ति को भी जब्त कर रही है।

इस नशे की लत के कारण प्रदेश के युवा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में 2017 के बाद बढ़े चिट्टे के मामले

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद ही चिट्टे के मामले ज्यादा बढ़े हैं। 2014 में हिमाचल में चिट्टा ग्राम के हिसाब से पकड़ा जा रहा था। उसके बाद ज्यादा मामले सामने आए।

जब्त किया गया चिट्टा

2014	557.440 ग्राम
2015	387.943 ग्राम
2016	634.654 ग्राम
2017	3.417 किलोग्राम
2018	7.707 किलोग्राम
2019	7.960 किलोग्राम
2020	6.751 किलोग्राम
2021	14.907 किलोग्राम
2022	11.519 किलोग्राम
2023	14.705 किलोग्राम

बॉर्डर एरिया पर हो सख्ती।

कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि कांग्रेस सरकार नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

तस्करों की जमानत न हो, इसको लेकर कानून कठोर किए जाने की जरूरत है।

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है।

बाहरी राज्यों से हो रही सप्लाई।

भाजपा राज्य मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से चिट्टे की सप्लाई हो रही है।

युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं।

प्रतिदिन चिट्टा तस्करों को पकड़ा जा रहा है।

थानों में सैकड़ों मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को अलर्ट करने की जरूरत है।

युवाओं को नशे के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। बॉर्डर एरिया में सख्ती की जरूरत है।

फर्म को 100 करोड़ एडवांस में रिलीज करने पर स्पष्टीकरण दें सीएम सुक्खू : राजेंद्र राणा

vkdlk gehjiqjA पूर्व विधायक और सुजानपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले शिमला नगर निगम में पानी की योजना के लिए एक फर्म को एडवांस में 100 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई।

15 मार्च को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का एलान करेगा।

मगर आनन–फानन में 15 मार्च को ही उक्त कंपनी को एडवांस में इतनी बड़ी राशि जारी कर दी गई, जो संदेह पैदा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि एडीबी के माध्यम से अनुमोदित प्रोजेक्ट के लिए एक फर्म को एडवांस में 100 करोड़ रुपये की राशि रिलीज करने और इसमें 10 करोड़ के किक बैक की चर्चाएं बाजार में हो रही हैं।

ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधा–सीधा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का बनता है।

राणा ने कहा कि उपरोक्त पानी की योजना के लिए तीन बार टेंडर आमंत्रित किए गए थे।

हर बार सिर्फ एक ही पार्टी ने इसमें टेंडर भरे।

विभाग के मंत्री ने फाइल पर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि एक ही फर्म को काम नहीं दिया जा सकता।

विभागीय मंत्री की टिप्पणी को नजर. अंदाज कर मामले को कैबिनेट में लाकर पास कर दिया गया और कंपनी को न केवल यह प्रोजेक्ट आवंटित कर दिया गया।

कांग्रेस ने कंगना रनोट को घेरा बोले सनातन धर्म में बीफ खाना पाप, भाजपा जवाब दे

vkdlk f'keykA हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीफ खाने को लेकर कंगना रनोट पर निशाना साधा है। सुक्खू ने कहा– सनातन धर्म में बीफ खाना पाप है। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू से पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह और बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी कंगना को निशाने पर ले चुके हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, भाजपा द्वारा गौमांस खाने वाले को प्रत्याशी बनाना चिंता की बात है। हिमाचल देवभूमि है। गौमांस खाना यहां की संस्ति के लिए चिंता का विषय है।

पूर्व विधायक ने भी कंगना की पवित्रता पर उठाए सवाल

वहीं बंबर ठाकुर ने कंगना रनोट की पवित्रता पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा– कंगना कहती हैं कि गाय का मीट टेस्टी होता है। जो गाय का मांस खाती हैं, उन्हें मंदिरों में ले जाकर सारे मंदिर अपवित्र कर दिए। उन्होंने पूछा कि आपकी पवित्रता भंग हुई है या आप अभी भी पवित्र है। उन्होंने कहा– इनके मुंह में राम राम बगल में छुरी।

इसे लेकर बंबर ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा कि गाय का मांस खाने वाली को आपने टिकट क्या सोचकर दिया। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी और कंगना अक्सर सनातन धर्म की वकालत करती रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस हिमाचल में कंगना को बीफ के बयान पर घेरने में जुट गई है।

कंगना बोली– अफवाह फैलाई जा रही

हालांकि कंगना रनोट ने एक ट्वीट करके बीफ खाने की बात को नकार दिया है। कंगना ने कहा– उन्होंने कभी भी न बीफ और न ही रेड मीट खाया। उन्हें बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। यह शर्मनाक है। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार कर रही हूं। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकतीं। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती।

कंगना के अकाउंट से किया गया पुराना ट्वीट, जिसमें बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है, यह बात कही गई थी।

विक्रमादित्य ने कंगना को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कहा

विक्रमादित्य सिंह ने कहा– कंगना को चुनाव में ऐसे मुद्दों का जवाब देना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन तक कह डाला है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में कंगना पर सियासी हमले और बढ़ेंगे। वहीं, कंगना अब भले ही इससे इनकार कर रही हैं, लेकिन विपक्ष कंगना को पुराने बयानों के आधार पर लेकर हमलावर हो गया है। खासकर मंडी सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह बीफ खाने के कंगना के बयान को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। यह बात उन्होंने साफ कर दी है।

10 से 30 फीसदी लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे कारोबारी एमएसपी पर

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश में एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य) पर 10 से 30 फीसदी लाभांश पर ही कारोबारी शराब बेच सकेंगे।

कर एवं आबकारी विभाग ने ओवरचार्जिंग रोकने को शराब ठेकों के बाहर विभिन्न श्रेणी के शराब ब्रांड को लेकर लाभांश की प्रतिशतता के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।

इस साल से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की तर्ज पर ठेकेदारों को खुद लाभांश तय करने का हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकार दिया है।

पहले शराब बोतलों पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) लिखा जाता था।

अब शराब की बोतलों पर न्यूनतम विक्रय मूल्य ही प्रिंट किया गया है। एमएसपी से बहुत ज्यादा मार्जिन पर शराब बेचने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है।

पड़ोसी राज्यों से मुकाबले और अवैध शराब की निगरानी को राज्य सरकार ने बीते दिनों आबकारी नीति में बदलाव किया था।

पहली अप्रैल से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो गई है। कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर किसी ठेके में महंगे दाम पर शराब बेची जा रही होगी तो ग्राहक दूसरे ठेके पर जाकर भी रेट पता कर सकेगा। इस परिस्थिति में ग्राहक को जिस ठेके पर सस्ते दाम पर शराब मिलेगी, वह वहीं से खगीदेगा। नए प्रावधान से इस साल करीब 2800 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान शराब से सरकार को 2600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।

विदेशी शराब पर 10, देसी शराब पर 30 फीसदी होगा लाभांश

विदेश से आने वाली व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, बीयर, वाइन और सिडार पर एमएससी से 10 फीसदी लाभांश तय किया गया है।

देसी शराब पर लाभांश 30 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। देश में बनी बीयर पर लाभांश 30 फीसदी तय किया गया है।

अंग्रेजी शराब पर लाभांश 15 और 30 फीसदी से ज्यादा नहीं।

देश में बनाई जाने वाली अंग्रेजी शराब को विभाग ने दो वर्गों में बांटा है। इसमें लो ब्रांड की शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड की शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया है।

लो ब्रांड की शराब वह होगी, जिसका एमएसपी 500 रुपये तक होगा।

500 रुपये से अधिक एमएसपी वाली अंग्रेजी शराब को हाई ब्रांड के तहत रखा गया है।

शराब का ब्रांड	एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य)
ब्लैक डॉग	1254
100 पाइपर	1228
ब्लैंडर प्राइड	856
8 पीएम प्रीमियम ब्लैक	551
रॉयल चौलेंज	560
ऑल सीजन	560
आफिसर च्वाइस	432

इन नंबरों पर कर सकते हैं ओवरचार्जिंग की शिकायत

कांगड़ा जोन : 01894 230186

– मंडी जोन : 01905 223499

– शिमला जोन : 0177 2620775

ठियोग में चिट्टा तस्कर के रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने चंडीगढ़–कोटखाई से 6 सप्लायर किए गिरतार

vkdlk fB;kx A शिमला जिला के कोटखाई में पुलिस ने चिट्टा सप्लायर के बड़े रेकेट का भंडाफोड़ किया है। ठियोग व कोटखाई पुलिस की टीम ने बीती शाम अलग अलग स्थान से 6 चिट्टा सप्लायर गिरतार किए। इनके खिलाफ ठियोग पुलिस थाना में एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। सूचना के अनुसार, पुलिस ने बीते 14 फरवरी को कोटखाई के परीक्षित को 12 ग्राम चिट्टा के साथ गिरतार किया था। ` पी कोटखाई के हैं, जबकि एक आरा. ` पी चंडीगढ़ का है।

इससे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी और छह अन्य आरोपी की गिरतारी के लिए पुलिस ने जाल बुना। इनमें पांच आरा.

लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए सरकार ने उद्योग से मांगा पैसा:जयराम ठाकुर

vkdlk lkyuA नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पैसा मांगा गया है। यह पैसा एक इंडस्ट्री से मांगा गया है। भाजपा सबूत इकठे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कबाड़ लेने के नाम पर एक विभाग खोल देना चाहिए और इसका मंत्री अलग से बना देना चाहिए। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है। मगर वह भूल रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं और हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। हमारा काम विरोध करना है। कांग्रेस के तीन लोग उन्हें छोडने को तैयार बैठे हैं। मगर उन्हें लोकसभा चुनाव तक की गोलियां दी जा रही हैं। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष तक चुनाव लडने से मना कर चुकी हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हालत है।

राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार में किसका कैसा सियासी कद, बेटियां मीसा और रोहिणी चर्चा में ?

ub fnYyh A लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में प्रमुख दलों ने अपने अधिकतर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हाल ही में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 22 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें लालू यादव परिवार से भी दो लोगों को टिकट मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की दो बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को राजद ने उम्मीदवार बनाया है।

मीसा भारती अभी राजद की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं रोहिणी आचार्य पहली बार सक्रिय राजनीति में उतरी हैं। उधर लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बिहार में राजद के विधायक हैं।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। पिता का नाम कुंदन राय और माता के नाम मरछिया देवी था। लालू प्रसाद यादव कुल सात भाई–बहन थे।

1. मंगरु यादव– लालू के भाई बहनों में मंगरु यादव सबसे बड़े थे। इनका परिवार आज भी लालू यादव के पैतृक गांव फुलवरिया में बसा है। बिहार में हुए पिछले पंचायत चुनाव में मंगरु यादव की पुत्रबधू मुखिया पद की उम्मीदवार थीं। हालांकि वो चुनाव हार गईं।

2. गुलाब यादव– लालू के भाई–बहनों में गुलाब दूसरे नंबर पर आते हैं। गुलाब यादव के दो बेटे और चार बेटियां हैं। 2011 में 75 साल की उम्र में गुलाब यादव का निधन हो गया था।

3. मुकुंद यादव– कुंदन राय और मरछिया देवी के तीसरे बेटे मुकुंद यादव रहे। मुकुंद पशुपालन विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। लालू यादव के साथ रह कर ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। मुकुंद के तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। 2013 में 75 साल की उम्र में मुकुंद का भी निधन हो गया था।

4. महावीर यादव– भाई–बहनों में महावारी यादव चौथे नंबर पर थे। ये भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी पत्नी का नाम गिरजा देवी था। महाव. ीर यादव के तीन बेटे और दो बेटियां थीं।

5. गंगोत्री देवी– लालू की इकलौती बहन गंगोत्री देवी थीं। 2018 में गंगोत्री देवी का निधन दिल का दौरा पडने़ के कारण हुआ था।

6. लालू प्रसाद यादव – गंगोत्री के बाद लालू प्रसाद यादव का नंबर आता है। लालू का जन्म 1948 में गोपालग. ंज जिले में हुआ था। लालू के साथ–साथ पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव की सात बेटियां और दो बेटे हैं। बेटों का नाम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव है। वहीं, बेटियों में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा सिंह, रागिनी यादव, हेमा, अनुष्का और राज लक्ष्मी हैं।

7. शुकदेव यादव– लालू के भाई–बहनों में शुकदेव यादव सबसे छोटे हैं।

लालू के बच्चे क्या करते हैं?

1. मीसा भारती – सबसे बड़ी मीसा भारती हैं। मीसा की शादी 1999 में सॉटवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई है। शैलेश अब खुद की कंपनी चलाते हैं। दोनों की दो बेटियां दुर्गा, गौरी और एक बेटा है। मीसा राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। 2014 में मीसा ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर मीसा को पाटलिपुत्र से टिकट मिला है।

2. रोहिणी आचार्या – दूसरी बेटी रोहिणी आचार्या हैं। रोहिणी भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। खासतौर पर पिता और भाई के लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। रोहिणी को सारण से उम्मीदवार बनाया गया है।

रोहिणी आचार्य 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर चर्चा में आई थीं। रोहिणी सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं लेकिन चुवान के लिए अब वह भारत आ चुकी हैं। रोहिणी की शादी 2002 में राव समरेश सिंह के साथ हुई है। समरेश भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं। दोनों के तीन बच्चे हैं।

3. चंदा – तीसरी बेटी चंदा भी काफी पढ़ी–लिखी हैं। चंदा ने पिता की तरह एलएलबी की पढ़ाई की है। चंदा की शादी 2006 में लाइट पायलट विक्रम सिंह से हुई है। दोनों का एक बेटा है।

4. रागिनी यादव – चौथी बेटी रागि. नी यादव हैं। रागिनी इंटरपास हैं। उन्होंने 12वीं के बाद रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के लिए एडमिशन लिया था। हालांकि, वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं। रागिनी की शादी 2012 में समा. जवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई।

5. हेमा यादव – पांचवी बेटी का नाम हेमा यादव है। हेमा ने बीआईटी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की है। हेमा का दाखिला मुख्यमंत्री कोटे से हुआ था। हेमा की शादी विनीत यादव से हुई है। विनित भी सक्रिय राजनी. ति में हैं।

6. धन्नु उर्फ अनुष्का राव – छठवीं बेटी धन्नु उर्फ अनुष्का राव हैं। अनुष्का की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव के साथ हुई है। चिरंजीव का परिवार अभी भी हरियाणा में सक्रिय राजनीति में है। अनुष्का ने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है।

7. राजलक्ष्मी यादव – सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव हैं। राजलक्ष्मी की शादी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है। तेज प्रताप भी सक्रिय राजनीति में हैं। सांसद भी रह चुके हैं। वहीं, राजलक्ष्मी ने स्नातक की पढ़ाई की है।

8. तेज प्रताप – भाइयों में सबसे बड़े तेज प्रताप ही हैं। तेज प्रताप ने इंटर तक की पढ़ाई की है। इनका जन्म 16 अप्रैल 1988 में हुआ था। तेज प्रताप बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तेज प्रताप वर्तमान में बिहार विधानसभा में हसनपुर से विधायक हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने थे।

9. तेजस्वी यादव – सबसे छोटे तेजस्वी यादव दो बार बिहार के उप–मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व भी किया है। वह बिहार विधानसभा में राघोपुर से विधायक हैं।

मानवाधिकार आयोग ठप न चेयरमैन और न ही दोनों सदस्य छह हजार से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं हरियाणा में

pMhx<A हरियाणा के मानवाधिकार आयोग में पिछले साल सितंबर से किसी भी केस की सुनवाई नहीं हुई है। मानवाधिकार हनन के पीड़ितों को सिर्फ तारीखें ही मिल रही हैं। पुराने केस तो लटके ही हैं। नए केसों की फाइलें भी लंबी होती जा रही हैं।

दरअसल, आयोग के पास न तो चेयरमैन और न ही सदस्य हैं। बीते साल सितंबर के बाद से मानवाधिकार आयोग में किसी केस की सुनवाई नहीं हुई है। नियुक्ति का विज्ञापन देने के बावजूद अब तक राज्य सरकार ने चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति नहीं की है। बताया जा रहा है कि विज्ञापन के बाद आवेदन भी आए।

हरियाणा के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि राज्य सरकार ने अभी तक माननीय अध्यक्ष/माननीय सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों में तारीखें दी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने बीते साल जून और फिर सितंबर में नियुक्ति को लेकर विज्ञापन भी निकाला। नियमों के मुताबिक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां उनके कार्यकाल खत्म होने के तीन महीने पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकार की ओर से बनाई गई अधिक. ारियों की एक कमेटी ने आवेदनों की जांच कर फाइल आगे भी बढ़ाई, मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई। आयोग के पास करीब दो हजार पुरानी शिकायतें लंबित हैं। वहीं, छह महीने में करीब चार हजार नई शिकायतें भी आई हैं। इन केसों की भी फाइल आगे नहीं बढ़ पाई।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग में एक चेयरमैन और दो सदस्यों की जगह है। आयोग के चेयरमैन जस्टिस एके मित्तल का कार्यकाल बीते साल अप्रैल में पूरा हो गया था। उसके बाद उनका चार्ज आयोग के ही सदस्य दीप भाटिया को सौंपा गया। कार्यवाहक चेयरमैन के तौर पर वह ही आयोग का कामकाज देख रहे थे। इस दौरान आयोग के दूसरे सदस्य केसी पुरी का भी कार्यकाल पूरा हो गया और वह आयोग से चले गए।

आयोग में सिर्फ दीप भाटिया ही बचे और किसी तरह से उन्होंने सितंबर तक आयोग का काम देखा और कई केसों का निपटारा भी किया। इस दौरान दीप भाटिया का भी कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद से आयोग में किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई है।

नियुक्ति में आचार संहिता की बाधा नहीं

हाईकोर्ट के एडवोकेट व चुनाव से संबंधित कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करे। लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। इनकी नियुक्ति में आचार संहिता की कोई बाधा नहीं है। पूर्व में कई बार अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि आचार संहिता की वजह से ढाई महीने प्रशासनिक कामकाज ठप नहीं रह सकते। चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर नियुक्तियां की जा सकती हैं। केरल सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर चेयरमैन की नियुक्ति की है।

पैनल करता है नियुक्ति

आयोग में चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति पैनल करता है। पैनल में हरियाणा के सीएम, विधानसभा स्पीकर, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। सीएम के पास ही गृहमंत्री का चार्ज है। इसलिए पैनल में तीन सदस्य ही शामिल होंगे। आयोग का चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट के जज हो सकते हैं। एक सदस्य हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या जिला सेशन के रिटायर्ड जज (सात–सात का अनुभव) हो सकते हैं, जबकि दूसरे सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके पास मानवाधिकार का व्यावहा. रिक अनुभव और ज्ञान हो।

यह सरकार जनहित की नहीं है। सरकार ने एक भी फैसला जनहित का नहीं किया है।

यह सरकार की नाकामी है कि इतने महीने बीतने के बावजूद आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। –भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष।

पूर्व सीएम मनोहर लाल व सीएम नायब सिंह सैनी अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का दर्द समझते हैं। उनकी हर समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है।

मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों को लेकर सरकार गंभीर है। आचार सं. हता की वजह से नियुक्तियों में कुछ समय लग सकता है। – सुदेश कटारिया, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, सीएम हरियाणा।

बसपा ने रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पर खेला दांव डॉ. मक्खन सिंह को संगरूर से मैदान में उतारा

pMhx<A बहुजन समाज पार्टी पंजाब ने संगरूर लोकसभा सीट से डॉ. मक्खन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर सिंह बेनिवाल ने यह जानकारी दी।

बेनिवाल ने कहा कि जल्द ही पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। सभी दावेदारों के नाम हाईकमान को भेजे हुए हैं और अंतिम निर्णय पार्टी प्रधान कुमारी मायवती द्वारा लिया जाना है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि डॉ. मक्खन सिंह बीएएमएसएएफ के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में बीएसपी पंजाब के महासचिव हैं।

डॉ. मक्खन सिंह स्वास्थ्य विभाग से उप निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी का दलित चेहरा पंजाब में दलितों को उपमुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करने का बदला लेगा। संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मजदूर वर्ग, गरीब, दलित और मुलाजिमों की एक बड़ी आबादी है, जो पूंजीवाद और जातिवाद के तहत उत्पीडऩ और अत्याचारों के शिकार हैं। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) डॉ. मक्खन सिंह के उम्मीदवार के रूप में संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ेगी।

इस अवसर पर प्रदेश महासचिव चमकौर सिंह वीर ने कहा कि दलित चेहरा डॉ. मक्खन सिंह को मैदान में उतारना बीएसपी आलाकमान का दूरदर्शी निर्णय है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। इस मौके पर उनके साथ विधायक डॉ. हरजोत कमल, विधायक सुखजीत सिंह काका लोहगढ़, विधायक दर्शन सिंह, पूर्व मंत्री मालती थापर, पूर्व विधायक विजय साथी, मोगा नगर निगम की मेयर नितिका भल्ला, चेयरमैन इंद्रजीत सिंह तलवंडी, चेयरमैन विनोद बंसल और अन्य नेता मौजूद थे।

सूटकेस में मिला टुकड़ों में कटा शव लुधियाना में रेलवे लाइन पर भी पड़े थे अंग,मृतक की पहचान नहीं

yfèk;kuk ¼iatkc½A लुधियाना में रेलवे लाइन से ब्रीफकेस में एक व्यक्ति का टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला है। आशंका है कि किसी ने व्यक्ति की हत्या करके शव को रेलवे लाइनों पर फैंक दिया, ताकि मामला आत्महत्या का नजर आए।

घटना की सूचना मिलते ही पहले आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद सिटी पुलिस को सूचित किया गया और डिवीजन नंबर छह की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। इसके अलावा ब्रीफकेस को भी लाईओवर से बरामद कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। ताकि हत्यारों का सुराग लगाया जा सके।

जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मी को रेलवे लाइन पर व्यक्ति के शरीर के टुकड़े पड़े दिखाई दिए और उसने इसकी जानकारी रेल पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की तो देखा कि लाइन के ऊपर बने लाईओवर पर खून से लथपथ ब्रीफकेस पड़ा था। इसमें शव को टुकड़ों में काट कर लाया गया था। आरोपी पूरे शव को रेल लाइन पर नहीं फेंक सका और कुछ टुकड़े ब्रीफकेस में भी पड़े थे। इससे साफ हो रहा था कि यह मामला हत्या का है। एसीपी इनवेस्टिगेशन राजकुमार का कहना है कि घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से भी हर आने जाने वाले की फुटेज को चौक किया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी इस बारे में पूछा जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही हत्यारे का पता कर लिया जाएगा। इसके अलावा मृतक की भी अभी पहचान नहीं हो सकी है।

इन गलतियों से चेहरे पर भर जाते हैं पिंपल्स क्रीम–लोशन से ना बने बात तो तुरंत करें ये इलाज

चेहरे पर मुंहासों को कम करने के लिए चेहरा धोने के लिए साबुन या फेसवॉश की जगह साफ पानी का इस्तेमाल करें। पिंपल्स को छेड़ें नहीं और गर्म तासीर वाली चीज़ें न खाएं। ग्रेप सीड और टी ट्री ऑयल से बनी क्रीम भी उपयोगी हो सकती है।

दाग चेहरे पर भले ही लग जाए, चरित्र पर नहीं लगने चाहिए। अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो पिंपल्स की वजह से चेहरे पर भी दाग नहीं लगेंगे। हां, इसके लिए चेहरे पर पिंपल्स यानी मुंहासों की एंट्री रोकनी होगी या फिर बहुत कम करनी होगी। यह कैसे होगा, क्या नहीं करना, अगर पिंपल्स निकल आएं तो क्या करना चाहिए? ऐसे तमाम अहम सवालों के जवाब देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स से लेकर जानकारी दे रहे हैं।

सबसे खास बातें

अपने चेहरे को दिन में 2 से 3 बार ज़रूर धोएं। खासकर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से आने के बाद।

धोने के लिए साफ पानी, सामान्य साबुन या वॉटर बेस्ड फेसवॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे साबुन से कई बार चेहरे पर ड्राईनेस हो जाती है।

कभी भी पिंपल्स को छेड़ें या फोड़ें नहीं। ऐसा करने से परेशानी में ही इज़ाफा होगा।

जब पिंपल्स निकल रहे हों तो ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों को खाने से बचें। मसलन ज़्यादा अंडे, नॉनवेज, ऑयली चीज़ें आदि।

कोशिश यह होनी चाहिए कि स्किन में मौजूद ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकलने का रास्ता बंद न हो। अक्सर सारी समस्या इस रास्ते के बंद होने से ही पैदा होती है।

दाग अच्छे तब होते हैं, जब वे आसानी से धुल जाते हैं। अगर न धुले तो दाग बुरे ही हैं। कई बार पिंपल्स की वजह से दाग चेहरे पर हो जाते हैं। वैसे ये मुंहासे सिर्फ टीन एजर्स को ही परेशान नहीं करते, ये कभी–कभी नवजात बच्चों को तो कई बार वयस्कों में 30 साल के बाद भी उभर आते हैं। हां, इनकी वजहें अलग–अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो चेहरे पर कभी काले दाग, कभी लाल दाग तो कभी गड्ढे नजर आ सकते हैं।

क्यों होते हैं पिंपल्स

कई लोग इसे मुंहासे तो कई फोड़ा–फुंसी भी कहते हैं। इंग्लिश में यह एक्ने के नाम से भी कुख्यात है। जहां तक आयुर्वेद की बात है तो इसे यौवन–कंटक कहा जाता है। पिंपल्स होने की सबसे बड़ी वजह ऑयल ग्लैंड के लो में रुकावट होना है। दरअसल, हमारी त्वचा में सिबेशस ग्लैंड (ऑयल ग्लैंड) मौजूद होता है। इससे सीबम (एक तरह का स्राव) निकलता है। यह ग्लैंड हमारे शरीर के बालों के साथ सुराखों में मौजूद होता है। सीबम में कलेस्ट्रॉल, वैक्स इस्टर्स (एक तरह की वसा) आदि मौजूद होता है। इससे निकलने वाला सीबम हमारी त्वचा को रुखी होने से बचाता है। साथ ही सीबम में एक कम शक्तिशाली एसिड भी मौजूद होता है। यह हमारी त्वचा पर एक फिल्म (पानी पर साबुन के बुलबुले) की तरह सुराखों को ढक लेता है और बैक्टीरिया व फंगस आदि के लिए एक रुकावट (बेरियर) के रूप में काम करता है। कई बार जब हम अपनी त्वचा चाहे चेहरे की हो या फिर किसी दूसरी जगह की, साफ नहीं रखते तो बालों के सुराखों में मौजूद ऑयल ग्लैंड से ऑयल यानी सीबम का स्राव कम या फिर बंद हो जाता है। इससे उन जगहों पर बैक्टीरिया आदि को बहुत ज्यादा संख्या में पनपने का मौका मिल जाता है। इससे इन ऑयल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है। नतीजे के रूप में सूजन के साथ मुंहासे उभर आते हैं। सिबेशस यानी ऑयल ग्लैंड चेहरे पर, कंधों पर, पीठ के ऊपरी हिस्सों, छाती और सिर पर ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। इसलिए मुंहासे भी इन्हीं हिस्सों में ही ज़्यादा होते हैं।

क्यों पड़ते हैं चेहरे पर मुंहासे और कैसे करें इन्हें काबू

सफाई न करना

पिंपल्स होने की यह सबसे बड़ी वजह है। कोई भी शख्स, किसी भी उम्र में हो, अगर अपने चेहरे को दिन में कम से कम 2–3 बार साफ पानी और साबुन या फेसवॉश से नहीं धोता तो मुमकिन है कि उसके चेहरे पर मुंहासे सूजन और खुजलाहट के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ जाएं। यहां इस बात का भी ध्यान रखना है कि दिनभर में अपना चेहरा साबुन या फेसवॉश के साथ 2–3 बार से ज़्यादा नहीं धोना है। कई लोग 8 से 10 बार चेहरा धोते हैं। इससे चीज़ें बेहतर होने के बजाए बिगड़ ही जाती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे डॉक्टर ने गुनग. ुने पानी से गरारे करने को कहा और हमने खौलता हुआ पानी मुंह में डाल लिया हो। हां, अगर सिर्फ सामान्य पानी से बिना साबुन या फेसवॉश के चेहरा साफ करना है तो यह संख्या 5–6 बार तक हो सकती है।

क्या करना चाहिए

दिन में कम से कम 2–3 बार अपने चेहरे को साफ पानी से ज़रूर धोना चाहिए। खासकर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से आने के बाद तो इसे बिल. कुल नहीं भूलना है। चाहें तो इसमें सामान्य साबुन या फेसवॉश का उपयोग भी कर सकते हैं। फेसवॉश वॉटर बेस्ड होने चाहिए। जब चेहरे पर तेल जैसी गंदगी जमा हो जाती है तो उसे हटाने के लिए ऑयल बेस्ड फेसवॉश की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार सामान्य साबुन से भी काम चल जाता है। इससे त्वचा पर मौजूद पोर्स खुल जाते हैं। हां, जिनकी त्वचा रूखी होती है, वे जब साबुन से धोते हैं तो त्वचा ज़्यादा रूखी हो जाती है। ऐसे में फेसवॉश बेहतर विकल्प होता है।

क्या–क्या हो फेसवॉश में

फेसवॉश मॉइश्चर युक्त हो।

उसमें फैटी एसिड जैसे तत्व शामिल हों।

जिन लोगों की स्किन ऑयली या फिर एक्नी प्रोन (जिन्हें ज़्यादा और जल्दी मुंहासे हो जाते हैं) है, उनके लिए फोम वाला फेसवॉश बेहतर रहेगा।

अगर मुंहासों के लिए किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बिना साबुन वाले क्लेंजर का इस्तेमाल करें।

मेकअप लगाकर ही सो जाना

कई लोग किसी पार्टी से या बाहर से घूम–फिरकर आने के बाद बिना चेहरा धोए ही सो जाते हैं। इससे चेहरे पर मुंहासों के पर्दापण की आशंका भरपूर हो जाती है। दरअसल, मेकअप लगाने के बाद चेहरे पर मौजूद ऑयल ग्लैंड के सुराख बंद हो जाते हैं। इससे वहां पर ऑयल जमा होने लगता है। फिर इन्फेकशन भी हो जाता है।

क्या करना है – मेकअप लगाकर कभी नहीं सोना। चेहरे को अच्छी तरह से साफ करना है। कई बार तो मेकअप की वजह से सुबह तक ही मुंहासे नजर आने लगते हैं।

टाइट कपड़े पहनना

पिंपल्स निकलने की एक वजह पसीने को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलना भी है। कई बार लोग टाइट कपड़े पहन लेते हैं, उसमें भी अगर वह कॉटन वाले न हों तो हवा पास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक तो पसीने के साथ सीबम के निकलने में परेशानी होती है, दूसरी ओर वह सूखता भी नहीं। नतीजा इन्फेक्शन हो जाता है।

क्या करना चाहिए– ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचें। ढीले कपड़े पहनें। अगर लगातार पसीना आ रहा है तो उसे साफ करते रहें।

प्यूबर्टी शुरू होना

लड़कों में 13–14 साल की उम्र में और लड़कियों में 12–13 साल की उम्र तक अमूमन यौवन की शुरुआत हो जाती है। इस उम्र में बड़े स्तर पर हॉर्मोनल बदलाव होते हैं। कई तरह के सेक्स हॉर्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। स्किन पर बालों के सुराख खुलने लग जाते हैं। दूसरे ग्लैंड्स की तरह ऑयल ग्लैंड भी बढ़ती उम्र के साथ ऐक्टिव होते जाते हैं। ऐसे में सही साफ–सफाई न होने पर इनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नतीजा पिंपल्स निकल आते हैं। स्थिति तब ज़्यादा खराब हो जाती है जब कई टीनएजर्स इन मुंहासों को फोड़ देते हैं या नोच देते हैं। कई बार इनमें मवाद भी भर जाता है। इससे चेहरे पर दाग, गड्ढे बन जाते हैं।

क्या करना चाहिए– जब भी कोई टीन ऐज की तरफ मुखातिब हो तो पैरंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को समझाएं कि किस तरह अपने चेहरे का ध्यान रखना है। कैसे साफ–सफाई करनी है। मुंहासों को फोडना तो बिलकुल नहीं।

पीरियड्स वाले दिन

कुछ लड़कियों में पीरियड्स शुरू होने से पहले या उस महीने की मेन्सेस खत्म होने पर मुंहासे निकलने की परेशानी हो सकती है। इसकी वजह हॉर्मोन में बदलाव, खानपान और साफ–सफाई ही है।

क्या करना चाहिए– पीरियड्स के दौरान भी चेहरे, कंधे आदि को ज़रूर साफ रखें। गर्म चीज़ें खाने से बचें।

कुछ महिलाओं में पीरियड्स की वजह से भी मुंहासों की परेशानी होती है। इसमें ओवरी में कई सिस्ट बन जाते हैं। इनकी वजह से हॉर्मोनल गड़बडियां हो जाती हैं। नतीजा पिपंल्स।

क्या करना चाहिए – इलाज कराएं। दवा सही वक्त पर लें। बाकी साफ–सफाई का ध्यान तो रखना ही है।

गलत खानपान

पिंपल्स को निकलने से रोकना हो या फिर पिपंल्स अगर हो जाए, उसे जल्दी ठीक करना। इन दोनों परिस्थितियों में खानपान का रोल बड़ा अहम है।

सेहत के लिए अच्छा है प्लांट प्रोटीन

मौजूदा दौर में सेहत बनाने का सबसे आसान नुस्खा है प्रोटीन। जिम ट्रेनर से लेकर डॉक्टर तक सब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे तर्क है कि ज्यादा प्रोटीन खाकर मोटापे को रोका जा सकता है। बॉडी फिटनेस के लिए प्रोटीन बड़े काम की चीज है। लेकिन नई स्टडी बताती है कि प्रोटीन का सेवन आपकी नींद भी हराम कर सकता है।

यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक हमारी सेहत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन एनिमल प्रोटीन आपकी नींद हराम कर सकते हैं।

प्लांट प्रोटीन सेहत के लिए क्यों अच्छा है?

मेडिकल जर्नल हॉर्वर्ड टीएच चान के मुताबिक, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से ही बना है। मसल्स, हड्डियां, स्किन, बाल और यहां तक कि बॉडी के हर टिश्यू में प्रोटीन होता है। इससे खास एंजाइम बनते हैं, जिनसे शरीर में कई केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये हीमोग्लोबिन भी बनाते हैं, जो ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हमारे शरीर में कम से कम 10,000 तरह के अलग–अलग प्रोटीन मौजूद हैं, जो हमें हमारे जैसा बनाए रखती हैं। हमारे शरीर का लगभग 20 फीसदी हिस्सा तो प्रोटीन से ही बना है।

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक हमारे शरीर को प्रतिदिन जितनी एनर्जी चाहिए, उसका 10 से 35 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन से पूरा होना चाहिए।

प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं–

एनिमल प्रोटीन

एनिमल प्रोटीन में हाई लेवल का सैचुरेटेड फैट होता है। अगर इसका लंबे समय तक सेवन किया जाए तो यह किसी को भी बीमार कर सकता है। सैचुरेटेड फैट के सेवन से ही आपकी नींद प्रभावित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। नींद डिस्टर्ब होने से क्रॉनिक डिजीज, स्ट्रेस और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

कई रिसर्च बताती हैं कि अगर प्रोटीन के लिए लंबे समय तक रेड मीट खाया जाए तो यह कैंसर का कारण भी बन सकता है। एनिमल प्रोटीन के सेवन से हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। प्लांट प्रोटीन इनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ ही ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं।

एनिमल प्रोटीन के सभी सोर्सेज बहुत पॉवरफुल होते हैं। इनसे कई बार इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, जितनी हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं होती है। इनके लगातार सेवन से जान जोखिम में पड़ सकती है–

एनिमल प्रोटीन के फायदे भी हैं

ऐसा नहीं है कि एनिमल प्रोटीन से सिर्फ नुकसान ही होते हैं। मछली खाने से दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन दुरुस्त बना रहता है और हार्ट डिजीज का खतरा भी टलता है।

एनिमल प्रोटीन से पतले मसल्स बनते हैं और बुढ़ापे में मसल्स कमजोर होने की समस्या भी नहीं आती है।

रात में नहीं खाना चाहिए मीट

सीनियर फिजिशियन कहते हैं कि डिनर में मीट खाने से बचना चाहिए। क्योंकि मीट में ढेर सारा प्रोटीन होता है और प्रोटीन को पचाने में लिवर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर रात में मेटाबॉलिक सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। चूंकि सोते समय बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है तो अपच की समस्या भी हो सकती है।

प्लांट प्रोटीन बेहतर विकल्प

प्लांट प्रोटीन से किसी तरह के नुकसान नहीं देखे गए हैं। असल में प्लांट प्रोटीन के सभी सोर्स लो प्रोटीन जेनरेट करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए प्लांट प्रोटीन का ही सहारा लिया जाए। दालें, फलियां, नट्स, सीड्स और साबुत अनाज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे शरीर को कई तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए सिर्फ एक तरह की दाल या फलियां खाने की बजाय सभी दालें, फलियां, सीड्स और नट्स खाने चाहिए।

प्लांट प्रोटीन के बड़े फायदे

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों का वजन मीट खाने वाले लोगों की तुलना में कम होता है। इन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। इससे स्ट्रोक, कैंसर और हार्ट डिजीज से मौत का खतरा भी कम हो जाता है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक साबुत अनाज, सब्जियां, मेवे और सीड्स का सेवन हार्ट अटैक के जोखिम कम करता है।

प्लांट प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल काबू में रखने में भी मदद करता है। वेब एमडी की एक स्टडी के मुताबिक प्लांट प्रोटीन के सेवन से टाइप–2 डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

प्लांट प्रोटीन के लगातार सेवन से वजन भी कंट्रोल करने में बना रहता है। अगर वजन न बढ़े तो कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा टल जाता है।

हमें अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, एक स्वस्थ व्यक्ति जितने किलोग्राम का होता है, उसे प्रतिदिन उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसे रोज 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए।

द इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के एक सर्वे की मानें तो भारतीयों में लगभग 80 प्रतिशत तक प्रोटीन की कमी है। इसका मतलब हुआ कि हमें या तो प्रोटीन का महत्व नहीं समझ आ रहा है या फिर हमारे खानपान में प्रोटीनयुक्त चीजों की कमी है।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी,शिक्षा,जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर,शिक्षक से परामर्श लें।

> **इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है।**
>
> **-डॉ० भीमराव अंबेडकर**

संपादकीय

सार्वजनिक सुरक्षा और कुत्तों की कुछ नस्लें

कुत्तों और समाज में उनके स्थान को लेकर भारत में जटिल दुविधाएं हैं। एक तरफ आवारा कुत्तों की समस्या है। देश भर में नागरिक अपनी आवासीय कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्तों के हमले के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन इससे अभी तक इन कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नगरपालिका कानूनों को लागू करने को लेकर कोई ठोस राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दूसरी तरफ, पालतू कुत्तों से जुड़ी बिल्कुल ही अलग श्रेणी की चिंताएं को सामने आई हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार के एक मंत्रालय और दो हाईकोर्टों का ध्यान उन पर गया है। जिन सवालों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है उनमें एक यह है कि क्या कुत्तों की कुछ नस्लें स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा क्रूर हैं। .षि मंत्रालय के पशु कल्याण और पशुपालन विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि क्रूर कुत्तों की कुछ नस्लों को पालतू जानवर के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विभिन्न नागरिक समूहों की ओर से इन कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले – कभी–कभी घातक भी– करने की शिकायत के बाद ऐसी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कुछ नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।

इनमें पिट बुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग जैसे मिश्रित और संकर (क्रॉसब्रीड) नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। इन नियमों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने की उम्मीद है। जिन कुत्तों को पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, उनका बंध्याकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आगे प्रजनन न हो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार के इस आदेश पर उस समय रोक लगा दी जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह आपत्ति जताई कि सरकारी विभाग का कदम एकतरफा है और इसमें विशेषज्ञ निकायों की व्यापक धारा को शामिल नहीं किया गया है। केनेल क्लब ऑफ इंडिया, जो शुद्ध नस्लों को पंजी.त करने वाली एक संस्था है, को इस निर्णय से समस्या हो सकती है। कुत्तों के स्वभाव से संबंधित सालों के अवलोकन और अंतर्दृष्टि से यह पता चला है कि उनकी क्रूरता और आक्रामकता पर्यावरणीय व व्यवहारिक, दोनों कारकों का नतीजा है। इस प्रकार उम्र, लिंग, आकार, अन्य कुत्तों के साथ मेल–जोल, प्रशिक्षण के तौर–तरीके और आक्रामकता को भड़काने वाली परिस्थितियां जैसे पहलू क्रूरता में योगदान करते हैं। जैसा कि मालूम है, कई देशों ने कुछ नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है या कुछ कुत्तों की नस्लों को पालने या रखने के लिए कड़ी शर्तें लगा दी हैं। इनमें से कोई भी देश भारत की तरह आवारा कुत्तों की इजाजत नहीं देता है और इसलिए उनके नियम भारत के मुकाबले सार्वजनिक सुरक्षा के कहीं उच्च मानकों पर आधारित होते हैं। इस लिहाज से, कुत्तों की कुछ नस्लों के अस्तित्व या अनुपस्थिति से सार्वजनिक सुरक्षा पर फर्क पडने की संभावना कम ही है। इसके बनिस्बत कुत्ते के मालिकों को होने वाले नुकसान के लिए ज्यादा उत्तरदायी बनाया जा सकता है। भले ही पालतू जानवरों को चुनने और पालने में व्यक्तिगत पसंद मायने रखती है, लेकिन यह किसी भी तरह से एक बेलगाम अधिकार नहीं है।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उग्रवाद

अगस्त 2021 में जब तालिबान काबुल में सत्ता में लौटा, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। ढाई साल बाद, अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमा दोनों देशों के बीच तनाव का एक सबब बन गया है। पाकिस्तान ने इस हते की शुरुआत में अफगान प्रांत पक्तिका और खोस्त में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम आठ नागरिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि वह तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को निशाना बना रहा है, जिसे वह अपने इलाके में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानता है। जवाबी कार्रवाई में, तालिबान ने सीमा पर स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। सीमा पर एक असहज शांति बनी हुई है और अफगान तालिबान का पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ जो सौहार्द था, वह अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान, जिसने 1990 के दशक में तालिबान के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने सालों से सुन्नी इस्लामवादी समूह का समर्थन किया है। वर्ष 1990 के दशक के अंत में, जब तालिबान सत्ता में आया था, तो पाकिस्तान औपचारिक रूप से उस शासन को मान्यता देने वाले सिर्फ तीन देशों में से एक था। इस्लामाबाद 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद वाशिंगटन के दबाव में तालिबान के खिलाफ हो गया, लेकिन उसने तालिबान का समर्थन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सहयोगी बनकर दो दशकों तक चतुराई से दोहरा खेल खेला। इस दौर में, समूचा तालिबान नेतृत्व बलूचिस्तान के क्वेटा में स्थित था। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान को तैयार किया था। जब 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी की अफगान सरकार गिर गई, तो पाकिस्तान को काबुल में एक दोस्ताना निजाम के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की उम्मीद थी। लेकिन हुआ ऐन उल्टा। ऐतिहासिक रूप से, अफगान सरकारों के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। खासकर, दोनों देशों के बीच की विवादित सीमा, डूरंड रेखा के मद्देनजर। जब तालिबान विद्रोही थे, तो उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत थी और पाकिस्तान को काबुल में काबिज सरकार के प्रतिकार के रूप में उनकी ज़रूरत थी। लेकिन आज काबुल में तालिबान की सरकार है। इसके अलावा, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, को मजबूत किया है।

133वीं अम्बेडकर जयंती 2024

अंबेडकर जयंती भारतीय संविधान के जनक डॉ. अंबेडकर के जन्मदिन का प्रतीक है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2024 को दलित आइकन के सम्मान में मनाई जाएगी, जिन्होंने अपना सारा काम और जीवन मजदूरों, महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. बीआर अंबेडकर ने न केवल देश को अपना संविधान दिया बल्कि भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और न्यायविद्, वह भारत में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक, दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे।

एक संक्षिप्त इतिहास

बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती की शुरुआत 1990 में डॉ. अम्बेडकर के जीवन का जश्न मनाने के लिए की गई थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक कम आय वाले परिवार में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वह कानून और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्व. विद्यालय दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वह एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और भारत के सामने मौजूद कई अन्य समस्याओं से लडने के लिए कड़ी मेहनत की।

अम्बेडकर जयंती के दौरान समारोह

पूरा देश डॉ. अम्बेडकर का जन्मदिन मनाता है, विशेषकर महिलाएँ, आदिवासी, दलित, मजदूर और अन्य सभी समुदाय जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और बदलावों को प्रेरित किया। भारत और दुनिया भर में स्थित अम्बेडकर के चित्रों और मूर्तियों पर फूलमालाएं चढ़ाकर उनका स्मरण किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग इस समाज सुधारक के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। हाल के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र ने भी अम्बेडकर जयंती मनाई है।

बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती पर, पूरे देश में कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों में कई अभ्यास और सांस्.तिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह दिन व्यापक रूप से मनाया जाता है क्योंकि अम्बेडकर का दर्शन आज भी वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है। भारत की सामाजिक–सांस्.तिक व्यवस्था को आकार देने में उनकी सक्रिय भूमिका के बिना, पुरातन मान्यताओं वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश बनने में कोई प्रगति करना असंभव होता।

जश्न मनाने का कारण

भारत द्वारा डॉ. अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का कारण भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के गरीबों के लिए उनके योगदान को याद करना और उनका सम्मान करना है। भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे उनका सबसे महत्वपूर्ण दिमाग था। उन्होंने शिक्षा के महत्व को फैलाने और कम आय वाले लोगों की वित्तीय स्थिति को समृद्ध करने के लिए 1923 में बहिष्.त हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन, पुजारी विरोधी आंदोलन, जाति–विरोधी आंदोलन आदि। उन्होंने समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीवन भर एक अर्थशास्त्री और समाज सुधारक रहे।

डॉ. बीआर अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान

डॉ. अम्बेडकर ने समाज में कई बदलाव किये जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कई आन्दोलन चलाकर दलित समुदाय के अधिकारा. ें की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से कुछ मूक नायक, समानता जनता आदि हैं। 1947 में देश को ब्रिटिश सरकार के प्रशासन से मुक्त होने के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था। 29 अगस्त 1947 को, वह बने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष।

उन्होंने देश का नया संविधान बनाया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चूंकि वह एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है, बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त,रुपये की समस्या इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास पुस्तकों के लेखक थे। ये आज भी भारत और दुनिया भर में युवा पीढ़ी के मन को प्रेरित करते हैं।

एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों को औद्योगिक और .षि गतिविधियों के विकास के लिए प्रेरित किया। वह भारत के महानतम लोगा. ें में से एक थे जिन्होंने लोगों को बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रेरित किया।

अम्बेडकर जयंती पर, भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की प्रथा है। भारत के कई लोग अंबेडकर जयंती 2024 पर सम्मेलनों और व्याख्यानों में भाग लेकर इस दिन का सम्मान करते हैं जो भारतीयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान खोजने के लिए समर्पित हैं। अन्य लोग इस दिन का उपयोग शांत ध्यान और चिंतन के लिए करने की योजना बनाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन पर भारत के सबसे महान दिमागों में से एक को सम्मान देने से बेहतर कुछ नहीं है।

अम्बेडकर जयंती, जिसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उनकी विरासत का सम्मान करें. इस वर्ष, 2024 में, हम उनका 133 वां जन्मदिन मनाएंगे, जो 14 अप्रैल, 2024 , यानी रविवार को मनाया जाएगा ।

भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, अम्बेडकर एक न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने अछूतों (दलितों) के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लडने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

पूरे देश में अक्सर सार्वजनिक अवक. ाश रहता है, इस दिन को समानता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नेता ने अपने पूरे जीवन में समानता की वकालत की और कानून की नजर में सभी भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार पर जोर दिया।

अम्बेडकर समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों, विशेषकर भारत में दलितों की दुर्दशा के उत्थान के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इसका उन पर बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि इसने उन्हें उनके हितों के लिए लडने और समानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।

भारतीय समाज में डॉ. अम्बेडकर के अपार योगदान और समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देते हुए, इस दिन को पूरे भारत में बहुत सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

हर साल 14 अप्रैल को क्यों मनाई जाती है अंबेडकर जयंती? जानिए इस दिन का महत्व

अम्बेडकर जयंती भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की जन्मजयंती दिवस के सम्मान में मनाई जाती है। हर साल 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन और विरासत को सम्मान में देश और दुनिया में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉ अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस जयंती को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भीम जयंती को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल, 2024 में, उनका 133वां जन्मदिन रविवार को देशभर में मनाया जा रहा है।

भारत के इतिहास में अहम शख्सियत रहे डॉ अम्बेडकर एक न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने अछूतों यानी दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं व श्रमिकों को अधिकारों दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने सभी भारतीय निवासियों की समानता और उचित उपचार के लिए लड़ाई लड़ी. उन्होंने जीवनभर समानता की वकालत की और कानून की नजर में सभी भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार पर जोर दिया. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान और आजादी के बाद डॉ. बीआर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी. हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों ने भारत में महिला सशक्तिकरण, समाज में महिला भागीदारी और लैंगिक समानता की नीव रखी. ऐसे तमाम समावेशी प्रयासों के लिए अंबेडकर जाने जाते हैं।

अंबेडकर जयंती का महत्व

डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करने से जुड़े रहे हैं, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों को अपनाता है। इस प्रयास में उनके योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ अम्बेडकर की अटूट लड़ाई और हाशिये पर पड़ी जातियों के अधिकारों के समर्थन का भारत में सामाजिक सुधारों और नीति के विकास पर अहम प्रभाव पड़ा है।

डॉ. अम्बेडकर अपने इस विचार के लिए जाने जाते हैं कि शिक्षा से परिवर्तन लाया जा सकता है और इसी से सामाजिक व आर्थिक बराबरी हासिल की जा सकती है। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।

हिंदू धर्म से अलग बताया बौद्ध, सिख और जैनियों को गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी कर कही ये बात

xkaËkhuxjA गुजरात गृह विभाग ने अपने उप सचिव विजय बधेका द्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर जारी किया, जिसमें गुजरात सरकार ने कहा कि वह बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म को हिंदू धर्म से एक अलग धर्म मानती है। इन तीनों में से किसी एक को अपनाने के इच्छुक हिंदुओं को गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के लिए कहा है।

बौद्ध, सिख, जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग– गुजरात सरकार

यह मामला तब सामने आया जब यह पाया गया कि बौद्ध धर्म में रूपांतरण की मांग करने वाले आवेदनों को नियमों के मुताबिक नहीं निपटाया जा रहा था। गुजरात में कई दलित हिंदू हर साल सामूहिक कार्यक्रमों में बौद्ध धर्म अपनाते हैं। सर्कुलर के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने देखा कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गुजरात के धर्म अधिनियम की मनमाने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया– सरकार

सर्कुलर में कहा गया कि यह देखने में आया है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन की अनुमति मांगने वाले आवेदनों में, नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, कभी–कभी, आवेदकों और स्वायत्त निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धार्मिक परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात सरकार मामले को लेकर सख्त

इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां रूपांतरण की पूर्व अनुमति के लिए आवेदन दायर किए गए थे, कार्यालयों ने यह कहते हुए उनका निपटारा कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 (2) के तहत, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के भीतर शामिल हैं और इसलिए आवेदक की आवश्यकता नहीं है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि कानूनी प्रावधानों के पर्याप्त अध्ययन के बिना धार्मिक रूपांतरण जैसे संवे. दनशील विषय पर जवाब देना न्यायिक मुकदमेबाजी में बदल सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी पूर्व अनुमति– गुजरात सरकार

गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 को लागू करते हुए, सर्कुलर में कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म में परिवर्तित करने/या करवाने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस कदम का राज्य में धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रमुख संगठन गुजरात बौद्ध अकादमी (जीबीए) ने स्वागत किया है।

सबसे युवा प्रधानमंत्री बने आयरलैंड के साइमन हैरिस – मोदी ने दी बधाई

McfyuA आयरलैंड की तस्वीर अब बदल सकती है, क्योंकि यहां लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद देश की कमान युवा हाथों में सौंपी जा रही है। सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 37 साल के हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बन गए हैं।

इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हैरिस पीएम बन सकते हैं और ऐसा ही हुआ। आयरलैंड की संसद में मंगलवार को हैरिस के समर्थन में 88 वोट पड़े। उन्हें गठबंधन की साझेदार पार्टियों फिएना फेल और ग्रीन पार्टी के अलावा कई निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिला।

भारत ने दी बधाई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर साइमन हैरिस को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, श्हम हमारे ऐतिहासिक संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास पर आधारित हैं।

भारत–आयरलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूं।

क्या है राजनीतिक अनुभव

साइमन हैरिस पार्टी की युवा शाखा से स्नातक होने के बाद, कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय हैं। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी न करने के बावजूद, उन्होंने जल्द ही खुद को एक समर्पित राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने पार्टी के अंदर विभिन्न भूमिकाएं निभाईं।

इसके बाद उनके अनुभव की बात करें तो हैरिस ने 2016 से 2020 के मध्य तक एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, जहां उन्होंने कोविड–19 महामारी के लिए देश की प्रतिक्रिया के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वराडकर की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभालते हुए, इन भूमिकाओं में उनके कार्यकाल ने उनकी नेतृत्व क्षमताओं और नीति विशेषज्ञता को आकार दिया है।

करियर पर एक नजर

हैरिस 16 साल की उम्र में फाइन गेल पार्टी से जुड़े थे।

वह मात्र 22 साल की उम्र में काउंटी काउंसिल बने।

2011 में 24 साल की उम्र में वह सांसद चुने गए थ।

2016 में कैबिनेट में बतौर स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया था।

इसके बाद उन्हें 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया।

अपने लोगों के लिए करूंगा काम

प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हैरिस ने कहा कि वह इस महान देश का प्रधानमंत्री चुना जाने को लेकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं हमारे लोगों की उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रोजाना मेहनत से काम करूंगा।

अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए दोबारा चुनी गईं जगजीत पवाडिया

okf'kxVuA भारत की जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुनी गई हैं।

उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामा. जिक परिषद (ईसीओएसओसी) द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक पोस्ट में कहा, आज, भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाडिया को न्यूयॉर्क में हुए चुनावों में 2025–2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए।

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना की और कहा कि अच्छा काम किया।

बता दें कि भारत को 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक है।

41 वोटों के साथ, पवाडिया ने कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 वोट मिले।

यह देखते हुए कि पांच सीटों के लिए 24 उम्मीदवार थे, चुनाव अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था।

पवाडिया 2015 से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य हैं।

उन्हें मई 2019 में 2020–2025 के पांच साल के कार्यकाल के लिए परिषद द्वारा फिर से चुना गया था। उन्होंने 2021–2022 के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

जगजीत पवाडिया का सफर

1954 में जन्मीं पवाडिया ने भारत सरकार में 35 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जिनमें भारत के नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (2006–2012); आयुक्त, कानूनी मामले (2001–2005); मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (1996–2001) शामिल हैं।

1968 में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र और अर्ध–न्यायिक निगरानी निकाय है। इसमें 13 सदस्य होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं और जो सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं।

चिकित्सा, औषधीय या फार्मास्युटिकल अनुभव वाले तीन सदस्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा नामित व्यक्तियों की सूची से चुने जाते हैं और 10 सदस्य सरकारों द्वारा नामित व्यक्तियों की सूची से चुने जाते हैं।

Vªai jk"Vªifr pqus x, rks l?kh; tkp ,tfl;ka tks ckbMu ds f[kykQ dj ldrh gS dkjokbZ

o,f'kxVuA अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आगामी चुनाव में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इससे जो बाइडन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन और उनके परिवार के खिलाफ चल रही संघीय जांच पर फोकस कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम के एक करीबी ने बताया कि जो भी बाइडन सरकार कर रही है, वही ट्रंप भी कर सकते हैं।

ट्रंप के खिलाफ 44 मामलों में चल रही है संघीय जांच

डोनाल्ड ट्रंप के एक अन्य करीबी ने बताया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संघीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि बाइडन को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि बाइडन ने जो किया है, वही उन्हें मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी संघीय अपराध के 44 मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 40 मामले गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित हैं और चार मामले 2020 के चुनाव में कथित धांधली से जुड़े हैं।

हालांकि तमाम आरोपों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद के तगड़े दावेदार हैं और जो बाइडन के साथ उनकी कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है।

जो बाइडन के खिलाफ चल रहे मामलों पर फोकस करेंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह अपने खिलाफ लगे संघीय आरोपों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन राज्यों की तरफ से लगे आरा. `प, खासकर न्यूयॉर्क में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

न्यूयॉर्क की अपीलीय अदालत में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक मामलों जैसे टैक्स में धोखाधड़ी, मानहानि और दुष्कर्म जैसे मामलों की सुनवाई हो रही है। वहीं जो बाइडन भी गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित मामलों को लेकर आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडन के खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी ला सकते हैं।

ट्रंप की राह आसान नहीं

डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बाइडन के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस पहुंचना उनके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। दरअसल जो बाइडन, ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

बाइडन ने ट्रंप के मुकाबले चुनाव कैंपेन के लिए 9 करोड़ डॉलर ज्यादा हासिल किए हैं। इस तरह से चुनावी कैंपेन के लिए दोनों नेताओं में चुनावी कैंपेन के लिए चंदे का अंतर बढ़ता जा रहा है। जो बाइडन और उनकी पार्टी ने मार्च तक 19 करोड़ डॉलर का चंदा हासिल किया।

वहीं इतने ही समय में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ 9.3 करोड़ डॉलर का ही चंदा मिला है।

तालिबान शासन में शिक्षा–रोजगार को तरस रही महिलाएं अफगानिस्तान में

dkcqyA अफगानिस्तान के तालिबान शासन में महिलाओं की स्थिति पर वैश्विक स्तर पर काफी चिंताएं जताई जा रही हैं।

इस बीच विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में अफगानिस्तान दुनिया के 178वें स्थान पर आता है। रिपोर्ट में कुल 190 देशों को शामिल किया गया था।

इन आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट

महिलाएं, व्यवसाय और कानून– 2024 के शीर्षक वाली विश्व बैंक की रिपोर्ट तीन प्रमुख मानदंडो पर केंद्रित है, जिसमें कानूनी ढांचे, नीति निर्माण और कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में महिलाओं की स्थिति पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति का आंकलन कार्यस्थल गतिशीलता, वेतन, स्वामित्व अधिकार, मातृत्व अधिकार, उद्यमिता, निवेश, बाल देखभाल, सुरक्षा, विवाह और सेवानिवृत्ति अधिक. ार जैसे कई बुनियादी सुविधाओं के आधार पर की गई थी।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान को कानूनी ढांचे के लिए 100 में से 20 अंक और नीति निर्माण के लिए 100 में से 13.3 अंक मिले हैं। सूची में बेल्जियम, डेनमार्क और कनाडा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

अफगानिस्तान में महिलाओं पर करीब 90 प्रतिबंध

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक की रिपोर्ट चिंता पैदा करती है क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं को वर्तमान में कई दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं को करीब 90 प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और मुक्त आंदोलन आदि शामिल हैं। अफगानिस्तान में पिछले दो वर्षों में निजी क्षेत्र और व्यवसायों में महिलाओं की रुचि बढ़ी है।

हस्तशिल्प की दुकान चलाने वाली सेदिका तुफान का कहना है कि हस्तशिल्प कार्याशालाओं में नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण महिलाओं का रोजगार और शिक्षा से वंचित होना है।

तालिबान का दावा– समृद्धि और सुकून भरा जीवन दे रहे

लड़कियों को पढने से रोकने, महिला अधिकारों के दमन और उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर देने की खबरों के बीच पिछले साल तालिबान ने दावा किया था कि उसके राज में महिलाओं की बेहतरी के लिए हरसंभव कदम उठाए गए हैं ताकि वह एक समृद्ध और सुकून भरा जीवन जी सकें।

तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने दावा किया कि इस्लामिक अमीरात शासन के दौरान महिलाओं को जबरन विवाह जैसी तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाई गई है।

स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर बलॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com